>

Title: Need for electronic transfer of wages, pensions, subsidies etc to the bank accounts of rural teachers, Anganwadi and ASHA workers.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति जी, भारतीय विशिÂष्ट प्रमाण पत्र प्राधिकरण कार्यबल ने ग्रामीण शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व आशा वर्कर्स को मिलने वाली तनख्वाहों से लेकर पेंशन व गरीबों को मिलने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी को सीधे इलेक्ट्रोनिक तरीके से उनके बैंक खाते में भेजने की सिफारिश की है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिहाज से यह एक वाकई अच्छा सुझाव है।

लेकिन यहां पर एक विरोधाभास है। इससे गरीबों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन पिछड़े राज्य जैसे यू.पी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, जहां पर गरीबों की संख्या, कुल आबादी का पचास फीसदी है, में विशिÂष्ट प्रमाणपत्र का कार्यक्रम शुरु नहीं करके एनपीआर का कार्य शुरु कर दिया गया है। इससे गरीबों के हक पर चोट पहुंचेगी। इन तीनों राज्यों की आबादी चार सौ मिलियन है जो देश की वर्तमान आबादी का लगभग चालीस फीसदी है। यदि आबादी का पचास फीसदी बेहद गरीब लोग हैं, तो उन्हें इस सुझाव के जरिए फायदा पहुंचाया जा सकता है। जहां विशिÂष्ट प्रमाण-पत्र प्राधिकरण को इन तीनों राज्यों में आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू करने की अनुमति न दे कर पहले एनपीआर का कार्य शुरू करा दिया गया है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां आधार कार्ड की तर्ज पर इसी तरह का कार्ड बनाने की पहल शुरू कर दी गई है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन राज्यों में विशिÂष्ट प्रमाण-पत्र प्राधिकरण को आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू करने की अनुमति दे, ताकि गरीबों को ज्यादा-से-ज्यादा लाभ मिल सके।